

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 10 जनवरी, 2008

विषय: जनपद टिहरी के स्थित नैनबाग में खाद्यान्न गोदाम के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थित नैनबाग में खाद्य गोदाम निर्माण के लिए परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, नई टिहरी द्वारा तैयार रु० 36.58 लाख के आगणन को वर्ष 2002-03 में T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त रु० 29.19 लाख अनुमोदित किया गया था, जिसके विरुद्ध रु० 10 लाख की प्रथम किस्त, शासनादेश दिनांक- 10.01.2003 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त योजना हेतु सी० एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित/संशोधित आगणन रु० 52.56 लाख के सापेक्ष T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत के अनुरूप रु० 45.40 लाख (रुपये पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वर्ष 2004-2005 में निर्माण कार्य के लिए रु० 10.00 लाख की द्वितीय किस्त, शासनादेश दिनांक-14.09.2004 तथा योजना की तीसरी किस्त रु. 20.00 लाख की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 16.01.2006 के द्वारा दी गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त योजना हेतु अवशेष एवं अन्तिम किस्त रु. 5.40 लाख (रुपये पांच लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर रखते हुए व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-16, उ०प्र० जल निगम, हरिद्वार को इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वह माह जनवरी, 2008 के अन्त तक उक्त खाद्यान्न गोदाम का निर्माण पूर्ण कराकर आयुक्त, खाद्य को हस्तान्तरित कराये जाने का प्रमाण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। पुनः पुनरीक्षित किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। योजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही पूर्ण किया जायेगा।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित किये जायेंगे तथा निर्माण किये जा रहे कार्यों में भूकम्प अवरोधी निर्माण तकनीक का समावेश अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
4. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।
5. वित्तीय स्वीकृति जिस मद हेतु दी जा रही है, उसी मद पर व्यय की जाय। स्वीकृत धनराशि कदापि अन्य मदों के उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
6. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई कार्यदायी संस्था का होगा।



7. यह सुनिश्चित किया जाय कि वित्तीय स्वीकृति जिस योजना के लिये दी जा रही हैं उसे उसी मद पर व्यय की जाये कदापि अन्य मदों के प्रयोजन में नहीं लायी जायेगी।

स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुदान संख्या 25-लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय-02-भण्डारण तथा भण्डारागारण-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-91-जिला योजना में गोदाम निर्माण कार्य-00-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1184/वित्त अनुभाग-5/2007, दिनांक- 02 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या-37 (1)/XIX/08-38 खाद्य/2002, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
7. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-16, उ०प्र० जल निगम, कन्सट्रक्शन एवी डिजाइन सर्विसेज, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग/गार्ड फाईल।
10. समन्वयक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

X.R.G.

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव।

5